

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(नं. 39/1987)

(जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित है)

(नं. 59/1994)

समाज के कमजोर वर्गों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्बलता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का प्रचलन सामान्य अवसर के आध पर न्याय का संवर्धन करे, लोक अदालत आयोजित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठ्ठासीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय-1

प्रारंभिक

- | | | |
|------------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1. | <p>(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987।</p> <p>(2) इसका विस्तार जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।</p> <p>(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निश् करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश। यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश है।</p> |
| परिभाषाएं | 2. | <p>(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—</p> <p>(क) "न्यायालय" के अन्तर्गत किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही है।</p> <p>(कक) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है।</p> <p>(ककक) "न्यायालय" से कोई सिविल दायिद्वक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के तात्पर्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई प्राधिकरण है।</p> <p>(ख) "जिला प्राधिकरण" से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्</p> |



- (खख) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 8क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।
- (ग) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है।
- (घ) "लोक अदालत" से अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है।
- (ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।
- (चच) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है।
- (छ) "स्कीम" से केन्द्रीय प्राधिकरण, किसी राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए तैयार की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है।
- (ज) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (झ) "राज्य सरकार" के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी है।
- (ञ) "उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 3क के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।
- (ट) "तालुक विधिक सेवा समिति" से धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।
- (2) इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियम या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबन्ध नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबन्ध, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

अध्याय-2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 3 (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और व्यक्तियों का पालन करने के लिए एक निकाय गठित करेगी जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा।



- (2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-
 - (क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा,
 - (ख) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायाधीश का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा और
 - (ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएँ हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- (3) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन, ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जाएँ, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएँ हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएँ।
- (4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियाँ और उनसे संबंधित अन्य शर्तों वे होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।
- (5) केन्द्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहण के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएँ।
- (6) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों व हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएँ।
- (7) केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सदेव वेतन, भत्तों और पेंशन भी है, भारत की संचित निधि में से अदा किए जायेंगे।
- (8) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और विनियम सदस्य-सचिव द्वारा उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभिप्रेमाणित किये जायेंगे।
- (9) केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य का कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि केन्द्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।



उच्चतम न्यायालय
केक सेवा समिति

- 3क (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जायेंगे, एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।
- (2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे -
- (क) उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष होगा और
- (ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (3) भारत का मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।
- (5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विहित किए जाए।
- (6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विहित की जाए।

केन्द्रीय प्राधिकरण
के कृत्य

- 4 (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा अर्थात्-
- (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत अधिकथित करना,
- (ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अत्याधिक प्रभावी और कम खर्चीली रक्रीमें तैयार करना,
- (ग) उसके व्ययनाधीन निधि का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण को निधि का आवंटन करना,
- (घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष महत्व वाले किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुद्दों में के रूप में आवश्यक कदम उठाना, और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना,



- (ड) ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों या श्रमिक कालोनियों में सामाजिक कमजोर वर्गों के उनके अधिकारों तथा साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षित प्रयोजन करने के दोहरे प्रयोजन से विधिक सहायता कैम्प आयोजित करना।
- (च) बातचीत, माध्यस्थता और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना,
- (छ) विधिक सेवाओं के क्षेत्र में निर्धनों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विश्लेषण में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना,
- (ज) संविधान के भाग 4क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति पंचनबद्धत सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक बातें करना,
- (झ) कालिक अंतराल पर विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानित करना और उसका मूल्यांकन करना और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित निधि से पूर्णतः या भागत क्रियान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना,
- (ञ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके व्ययनाधीन स्वी गई स्कीमों में से विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान देना,
- (ट) भारतीय विधि परिषद के परामर्श से वैज्ञानिक विधिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन का संवर्धन करना तथा विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लिनिकों की स्थापना और उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना,
- (ठ) लोगों के बीच विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता के प्रसार और विशिष्ट समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमों द्वारा गारण्टी किए गए अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के बारे में साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और अभ्युपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना,
- (ड) मूलभूत स्तर पर, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियाँ और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्यरत स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना और
- (ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ, तालुक विधिक सेवा समिति में



स्वच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यक्रमों को सहायित और मॉनिटर करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना।

केंद्रीय प्राधिकरण
का अन्य-अभिकरणों
के समन्वय से कार्य
करना।

6.

केंद्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जहां भी उपयुक्त हो अन्य सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के विधिक सेवा के उद्देश्य के सर्वधन के कार्य में लगी अन्य (संस्थाओं) के समन्वय से कार्य करेगा।

अध्याय-3

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण का गठन

6.

- (1) प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।
- (2) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-
 - (क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा।
 - (ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त या सेवानिपुण न्यायमूर्ति जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा, और
 - (ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएँ हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँ और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएँ।
- (3) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएँ, या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा, उसे समनुदिष्ट किए जाएँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश की पक्ति से नीचे का न हो, राज्य प्राधिकरण का सदस्य-सचिव नियुक्त करेगी।



परन्तु राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और परामर्श बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति उस प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह इस उपधारा के अधीन उस रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह न हों।

- (4) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधिया और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।
- (5) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।
- (6) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों से हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।
- (7) राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे।
- (8) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्पन्न रूप से प्राधिकृत राज्य प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।
- (9) राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि राज्य प्राधिकरण में कोई लिखित है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

राज्य प्राधिकरण
के कृत्य

7. (1) राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केन्द्रीय प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे।
- (2) राज्य प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा अर्थात्—
- (क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन आधिकारिक मानदंडों की पूर्ति करते हैं,
- (ख) लोक अदालतों का जिनके अन्तर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, संचालन करना,



- (ग) निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, और
 (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विनियमों द्वारा, नियत करें।

राज्य प्राधिकरण
 या अन्य अभिकरणों
 आदि के साथ समन्वय
 से कार्य करना और
 केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा
 दिये गये निर्देशों
 के अधीन होना।

8. (1) राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों गैर-सरकारी
 स्वैच्छिक समाज या संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धन के लिए विधिक सेवा
 के उद्देश्य संदर्भन के कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय समुचित
 रूप से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों से भी मार्गदर्शित होगा जो केन्द्रीय
 प्राधिकरण लिखित रूप में दे।

उच्च न्यायालय
 विधिक सेवा
 समिति।

- 8.क (1) राज्य प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के
 प्रयोजन के लिए, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रयोजित किए जायें, उच्च न्यायालय के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसे
 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।
 (2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो उच्च न्यायालय के मुख्य
 न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे:-
 (क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष हो, और
 (ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएँ हों जो राज्य
 प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अध्यापित की जाएं।
 (3) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा
 जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएँ हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित
 की जाएं।
 (4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियों और उनसे सम्बंधित अन्य शर्तें वे
 होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अध्यापित की जाएं।
 (5) समिति अपने कृत्यों को दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य
 कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य
 न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

जिला विधिक सेवा
 प्राधिकरण।

9. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण को प्रदत्त या
 समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए उच्च
 न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक
 निकाय का गठन करेगी जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा।
 (2) जिला प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-



- (क) जिला न्यायाधीश जो उसका अध्यक्ष होगा और
- (ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएँ हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँ और जो उस सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये जायें।
- (3) राज्य प्राधिकरण, उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो ऐसे अध्यक्ष द्वारा उसी समनुदिष्ट किए जाएँ, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को जो जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य कर रहे अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पदवी से नीचे की पदवी का न हो जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।
- (4) जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएँ।
- (5) जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएँ।
- (6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएँ।
- (7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को राशेय वेतन, भत्ते और 'शन' भी हैं, राज्य की सचित विधि में से अदा किए जायेंगे।
- (8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा समक्ष रूप से प्राधिकृत उस प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।
- (9) जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अपविधान्य नहीं होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसका गठन में कोई त्रुटि है।

जिला प्राधिकरण
के कृत्य

- 10 (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करे जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएँ।
- (2) जिला प्राधिकरण उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन कर सकेगा, अर्थात् :-
- (क) तालुक विधिक सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों



का समन्वय करना,

- (ख) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना और
(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य प्राधिकरण, विनियमों द्वारा नियत करें।

जिला प्राधिकरण का 11
अन्य अभिकरणों के
समन्वय से कार्य करना
और केन्द्रीय प्राधिकरण,
आदि के निर्देशों के
अधीन रहना।

जिला प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धनों को विधिक सेवा के उद्देश्य से सार्थक कार्य में लगी अन्य संस्थाओं के समन्वय से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों द्वारा मार्ग दर्शित होगा जो उसके केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं।

तालुक विधिक सेवा
समिति

11क (1)

- राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुक या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।
(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,
(क) इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला उच्च न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा, और
(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अहंताएं हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएं।
(3) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जायें।
(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।
(5) समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जायेंगे।

तालुक विधिक
सेवा समिति के कृत्य

- 11ख. तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्—
(क) तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,
(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और
(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समादिष्ट करे।



अध्याय 4 विधिक सेवा के लिए हक

विधिक सेवा देने
के लिए मानदण्ड

- 12 प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है
- इस आधेनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा यदि ऐसा व्यक्ति --
- (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है,
- (ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में मथानोदष्ट मानव दुय्यंजहार या बेगार का सत्ताया हुआ है
- (ग) स्त्री या बालक है
- (घ) मासिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है
- (ङ) भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन रागया हुआ व्यक्ति है या कोई औद्योगिक कर्मकार है या
- (च) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधेनियम 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या नि गेर
- मनोविकिरीय अस्वताल या मनोविकिरीय परिधायं गृह में आभरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है या
- (ज) ऐसा व्यधित है जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो 25 हजार रुपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो राज्य सरकार विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो 25 हजार रुपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है

विधिक सेवा
लिए हक

- 13 (1) वे व्यक्ति जो धारा 12 में निर्नीदष्ट मानदण्डों में से सभी या किसी को पूरा करते हैं विधिक सेवाए प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे परन्तु यह तब जब कि संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजित या प्रतिस्था करने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला है
- (2) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथपत्र विधिक सेवा हक के लिए उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकरण के पास ऐसी शपथपत्र अविशवास करने का कारण न हो



अध्याय-5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केंद्रीय सरकार
द्वारा अनुदान

14

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए ढीक समझो।

राष्ट्रीय विधिक
सहायता निधि

15

केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा और उस निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी अर्थात् -
धारा 14 के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदत्त राशि के अन्तर्गत

कोई ऐसा अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण को दिए जायें

केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त की गई रकम

किया जाएगा, अर्थात् -

इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित विधिक सेवाओं के दायरे अन्तर्गत अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण को दिए गये अनुदान भी है

म न्यायालय निष्पक्ष सेवा समिती द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का अन्तर्गत कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केंद्रीय प्राधिकरण से अनिवार्य है

राज्य विधिक
सहायता निधि

16

राज्य प्राधिकरण राज्य विधिक सहायता निधि नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी अर्थात्

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सन्तुष्ट राशि और नाराजि या दिये गये

कोई ऐसा अनुदान या दान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण को, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये जायें

राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्य श्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम

राज्य विधिक सहायता निधि का उपयोग निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा अर्थात्



धारा 7 में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्च

कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति राज्य प्राधिकरण से अपेक्षित है

जिला विधिक
सहायता निधि

17

सदत सभी घनराशि का दिए गये अनुदान

अथ

श्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

जाएगा अर्थात्-

धारा 10 और धारा 11 ख में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्च

लेखा और सपरीक्षा

18

परामर्श से, विहित की जाए।

(2)

और महालेखा परीक्षक को सटय होगा।

(3)



निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

- (4) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा उन पर किए गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा उन पर राज्य सरकार को अर्पित किया जायेगा।
- केंद्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और समीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात, यथा शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।
- (6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त लेखा और समीक्षा रिपोर्ट उन्हें प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 6

लोक अदालत

लोक अदालतों
का आयोजन

19 (1)

का आयोजन कर सकेगी।

- (2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उनमें से किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उनमें से
- (क) संघीय या संघीय न्यायिक अधिकारियों और
- (ख) अन्य व्यक्तियों
- से मिलकर बनेगी जिनमें ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।
- (3) वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिवक्ता के परामर्श से विहित की जाए।



(2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अज्ञान से होगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विहित की जाए।

(5) किसी लोक अदालत को उस न्यायालय के विचारों के लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है।

(6) समक्ष लांबित किसी मामले की वास्तव या

(11) उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी ऐसे विषय की वास्तव में उसकी समक्ष नहीं लाया गया है।

किसी विवाद का अकारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या पारस्परिकरण करने की अधिकारिता होगी -

परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी जो किसी विधि के अधीन प्राप्तीय नहीं है।

लोक अदालतों
द्वारा मामलों
का सञ्चालन

20 (1) जहाँ धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में -
(i) उस मामले को पारस्परिकरण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए-

उसके पक्षकार सम्मत हैं या

उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्टया समझान हो जाता है कि ऐसे पारस्परिकरण की संभावना है या

(ii) न्यायालय का समझान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा ज्ञान दिए जाने के लिए स्वीकृत मामला है तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा।

परन्तु खंड (i) के उपखंड (a) या खंड (ii) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को ऐसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का सुविधापूर्ण अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा अन्यथा नहीं।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 19 की उपधारा (i) के अधीन लोक अदालत को आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले में किसी एक पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना आवश्यक है ऐसे मामले को लोक अदालत की अवधारणा के लिए निर्दिष्ट कर सकती।

परन्तु लोक अदालत को कोई मामला अन्य पक्षकार को सुनवाई का सुविधापूर्ण अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा अन्यथा नहीं।



3. जहाँ कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट विषय जाता है या जहाँ उपधारा (2) के अधीन उस कोई निर्देश किया गया है, वह लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या परिनिवारण करेगी।
- (4). प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त किसी निर्देश या अवधारण करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या परिनिवारण करने के लिए अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय साम्या के जूना और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।
- (5). जहाँ लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिवारण नहीं हो सका है, वह उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय का जिससे उपधारा 1, के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था विधे के अनुसार निपटारने के लिए लौटा दिया जायेगा।
- जहाँ लोक अदालत द्वारा कोई अधिनिर्णय इस आधार पर नहीं किया जाता है कि पक्षकारों के बीच उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिवारण नहीं हो सका है, वह वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय से उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

(7). उपधारा (1) के अधीन ऐसा निर्देश करने से पूर्व कार्यवाही की गई थी।

लोक अदालत
की अधिनिर्णय

21. (1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय यथारिथति निम्नलिखित न्यायालय की लिखी या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहाँ किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसके निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता कराया या परिनिवारण किया गया है, वह ऐसे मामले में लोक अदालत न्यायालय फीस न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन उपबन्धित शर्तों से लाटा दी जाएगी।

2. पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

लोक अदालत
की शक्तियाँ

22. (1) लोक अदालत की, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन से निम्नलिखित न्यायालय में, निम्नलिखित में से किसी विषय की वास्तविक विचारण करते समय निर्रत होती है, अर्थात् -



- १ किसी साक्षी को समन कराना हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना
- २ किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसकी पेश किया जाना
- ३ शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना
- ४ 'अपनी न्यायाधीश' के द्वारा प्रत्येक लोक अदालत को उराके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी प्रक्रिया विभिनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी
- ५ 'अपनी न्यायाधीश' के द्वारा प्रत्येक लोक अदालत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा

अध्याय 7

प्रकीर्ण

प्राधिकरणों,
समितियों और
लोक अदालतों
के सदस्यों और
कर्मचारियों का
लोक सेवक होना

23

अपनी प्रक्रिया में लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाएगा। लोक अदालतों के सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

सदभावपूर्वक की
की गई कार्रवाही
के लिए संरक्षण

24

कई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही -
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार
सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों,
या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों



- (घ) उपखण्ड (ख) से उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी मुख्य सरक्षक कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

अधिनियम का
अध्यारोही प्रभाव
होना।

25. इस अधिनियम के उपबन्धों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उपासो असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

केन्द्रीय सरकार
करने की शक्ति।

26. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उपासो असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

- (2) यथाशीघ्र संसद के प्रथम सदन के समक्ष रखा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति

27. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा बना सकेंगी।
- (2) ऐसे नियमों में निम्नांकित सभी या किसी विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है -

- (क) धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अहताएँ
- (ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की अनुभव और अहताएँ तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य
- (ग) धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदव्यवस्थाएँ तथा उनसे सम्बंधित अन्य शर्तें
- (घ) धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य



कर्मचारियों की संख्या

- (ड) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,
- (घ) धारा 3 क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,
- (ङ) धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं,
- (च) धारा 3 क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते,
- (ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उनकी वार्षिक आय की उच्चतम सीमा,
- (झ) धारा 18 के अधीन वह रीति जिसमें केन्द्रीय प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के लेखा रखे जायेंगे,
- (ट) धारा 19 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,
- (ठ) धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अन्य विषय,
- (ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति

28. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्वी के परामर्श से अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:-
- (क) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,
 - (ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य,
 - (ग) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें:-
 - (घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,
 - (ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य



- कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते
- (ब) धारा 8 क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अहंताएँ,
- (छ) धारा 8 क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें और उन्हें सदैव वेतन और भत्ते,
- (ज) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अहंताएँ
- (झ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या
- (ञ) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते
- (ट) धारा 11क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अहंताएँ
- (ठ) धारा 11 क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या
- (ड) धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते
- (ढ) यदि नामित उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा के लिए किसी व्यक्ति को हक़ार बनाने के लिए उसकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा,
- (ण) धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अहंताएँ,
- (त) कोई अन्य विषय जिसे शिष्ट किया जाना है या विहित किया जाए।

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

29. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टता और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा अर्थात्:-
- (क) धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति



की शक्तियाँ और कृत्य

- (ख) धारा 3 क की उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें।

राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

- 29क. (1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टता और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषयों के लिए उपबन्ध दिए जा सकेंगे, अर्थात्—
- (क) धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा पालन किये जाने वाले अन्य कृत्य,
- (ख) धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियाँ और कृत्य,
- (ग) धारा 8 क की उपधारा 2 खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएँ,
- (घ) धारा 8 क की उपधारा (4) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,
- (ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,
- (च) धारा 8 क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएँ,
- (छ) धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा पालन किये जाने वाले अन्य कृत्य,
- (ज) धारा 11 क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उनसे संबंधित अन्य शर्तें।

नियमों और विनियमों का रखा जाना

30. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, पेश करने की अवधि के लिए रखा जाएगा। का अवधि यह सत्र में समाप्त हो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों में ठीक बाद के सत्र में अधिनियम के पूर्णतः नए सदन उस नियम



का विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

* केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध विधायक अध्याय III दिनांक 9 नवम्बर, 1995 से प्रवृत्त किये गये।
* केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्वय III के उपबन्ध दिनांक 5 जुलाई, 1996 से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त किये गये।